elect, in such manner as directed by the Chairman, one Member from amongst the Members of the House to be a member of the Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management, constituted under the said Act."

The question was put and the motion was adopted.

PANEL OF VICE-CHAIRPERSONS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, taking note of the non-availability of some Members in the panel, the following hon. Members are nominated to the panel of Vice-Chairpersons:-

1. Shri Pramod Tiwari
2. Dr. Sangeeta Balwant
3. Shrimati Dharmshila Gupta
4. Shrimati Maya Naroliya

Hon. Members, ten notices have been received under Rule 267.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.)*

REGARDING NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The notices of Shri Sukhendu Sekhar Ray, Shrimati Mausam B Noor, Ms. Sushmita Dev, Shri Pramod Tiwari have demanded discussion over the alleged lapse of Election Commission in issuance of multiple duplicate electors photo identity card across the States. The notices of Shri P. Wilson, Dr. V. Sivadasan have demanded discussion over the concerns regarding upcoming delimitation exercise to Southern States. The notice of Shri Samik Bhattacharya demands discussion over increasing instances of atrocities against SCs, STs and OBCs in the State of West Bengal. The notice of Shri Sandosh Kumar P demands discussion over adverse impact on account of the deal of two Indian telecom companies with Starlink. The notice of Shri Sanjay Singh demands discussion over the increase in crimes and deteriorating law and order situation in Delhi. The notice of Shri Haris Beeran demands discussion over the increasing instances of drug addiction amongst youth and students in the State of Kerala.

Hon. Members may recall the detailed rulings on the Rule 267 imparted by the Chair on 8th December, 2022 and 19th December, 2022. The same have been reiterated a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Chair, the same are declined. ...*(Interruptions)*... Please sit down. Now, Matters raised with permission. Shri Iranna Kadadi. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. Please take your seat. Now, Shri Iranna Kadadi – Concern over increasing cases of fake surgeries in the country. ...*(Interruptions)*... Please speak. श्री ईरण्ण कडाडी , केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Concern over increasing cases of fake surgeries in the country

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्णाटक) **:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। डॉक्टरों को सदियों से भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक व्यावसायीकरण ने इस पेशे की गरिमा को संकट में डाल दिया है। पहले जहाँ चिकित्सा एक सेवा थी, वहीं अब यह एक लाभ केंद्रित प्रणाली बन गई है। मेडिकल कॉलेजों की ऊँची फीस, निजी अस्पतालों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण ने इसे बाज़ार आधारित प्रणाली में बदल दिया है। नी रिप्लेसमेंट, केटेरेक्ट सर्जरी, गाल ब्लेडर रिमूवल, एंजियोप्लास्टी और स्पाइनल सर्जरी जैसी प्रक्रिया अब कई जगहों पर बीमा राशि का अनुचित लाभ उठाने के लिए की जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, कई निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की आय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी सर्जरी करवाते हैं। महोदय, उन्हें टारगेट दिए जाते हैं, जिससे मरीजों को अनावश्यक ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना शुरू की है, लेकिन अब इसमें भी फर्जी सर्जरी और फर्जी क्लेम के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा फर्जी डॉक्टर्स और अप्रशिक्षित चिकित्सक बिना योग्यता के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। महोदय, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे अनधिकृत चिकित्सकों और क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ...(**व्यवधान**)... महोदय, फर्जी सर्जरी को रोकने के लिए निजी अस्पतालों का नियमित ऑडिट अनिवार्य किया जाए और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चिकित्सा पेशे की गरिमा भी बनी रहे। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...